RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

■ INDORE ■ 26 JANUARY 2022 TO 01 FEBRUARY 2022

www.Indianplasttimes.in

INDIAN PLAST TIMES

■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 21 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

देश में पहली बार एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और लुब्रिकेंट का ट्रायल शुरू Page 2

Budget 2022: बजट 2022 से हैं ये 22 बड़ी उम्मीदें Page 4

ऑस्ट्रेलिया के ब्लैकमोर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की Page 7

editoria!

अमीरों पर बढ़े टैक्स

दुनिया के सौ से ज्यादा अरबपति एक अपील लेकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि उन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, वह काफी नहीं है। उनसे और ज्यादा टैक्स लिया जाए और अभी लिया जाए। पहली नजर में अजीब सी लगती इस अपील के पीछे कुछ ही दिनों पहले आई वह स्टडी रिपोर्ट है, जो बताती है कि दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल चैरिटी ऑक्सफैम द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के दस सबसे अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति महामारी वाले उन दो वर्षों में दोगुना बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर ली, जब दुनिया के ज्यादातर लोग तरह-तरह की तकलीफों से गुजरते हुए गरीबी में और गहरे धंस गए। ऐसे में इन 102 अरबपतियों ने अपनी इस साझा अपील के जरिए यह बात उठाई है कि मौजूदा टैक्स सिस्टम न्यायपूर्ण नहीं है। इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है, जिससे अमीर और अमीर, गरीबी और गरीब होते जाएं। इसीलिए इस टैक्स सिस्टम में बदलाव लाते हुए अमीरों पर और ज्यादा टैक्स लगाने की पहल की जानी चाहिए। हालांकि कहां कितना टैक्स लगाना है, यह हर देश की सरकार अपने हिसाब से ही तय कर सकती है, फिर भी इस पत्र में सुझाव के तौर पर 50 लाख डॉलर तक की संपति वालों पर 2 फीसदी, 5 करोड़ डॉलर तक पर तीन फीसदी और सौ करोड़ से ऊपर की संपत्ति वालों पर पांच फीसदी का वेल्थ टैक्स लगाने की बात कही गई है। अगर इतना वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो सालाना इतनी रकम इकट्ठा हो जाएगी कि न केवल सबको मुफ्त टीका लगाया जा सकेगा बल्कि सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही कम और मध्यम आय वर्ग के देशों के 3.6 अरब लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी दी जा सकेगी। अपने देश में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। ऑक्सफैम की ही रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 98 सबसे अमीर भारतीयों के पास इतनी संपत्ति है जितनी कि सबसे गरीब 55 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। और अगर सिर्फ इन 98 भारतीयों की संपत्ति पर चार फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो उससे इतना पैसा आ जाएगा है कि अगले 17 साल तक मिड-डे मील स्कीम बिना किसी बाहरी मदद के चलती रहेगी। देश में सिर्फ एक फीसदी संपत्ति कर से पूरी स्कूली शिक्षा का खर्च निकल सकता है। सचमुच वक्त आ गया है, जब सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए।

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद क्यों स्थिर हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

राहत या चुनाव बाद आने वाली है आफत?

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जारी है। कच्चे तेल के दाम पिछले सात साल का रिकार्ड तोड़ते हुए 85 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पर पिछले करीब ढाई माह से पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया है। तत्कालिक तौर पर भले ही यह राहत दिख रही हो, लेकिन चुनाव बाद पेट्रोल-डीजल के दाम में करीब 5 रुपये की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर चार नवंबर 2021 को उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। इसके बाद दाम स्थिर हैं। हालांकि, इसके बाद कई राज्यों में वैट कम करने से दाम कम हुए जरुर हुए है, पर कोई वृद्धि नहीं हुई। विपक्ष इसे चुनाव से जोड़ रहा है। क्योंकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार दम बढ़ रहे हैं। अक्तूबर 2014 के बाद कीमत रिकार्ड स्तर पर हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढने के बावजूद कीमत स्थिर रही थी। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव के दौरान भी दाम स्थिर रहे थे। पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त 27 फरवरी से 23 मार्च तक पेट्रोल के दाम 91.17 रुपए और डीजल की कीमत 81.47 पर स्थिर रही थी। जबकि, इस दौरान कच्चा तेल मंहगा हुआ था। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ो के मुताबिक जनवरी 21 में कच्चे तेल के दाम 49.84 डॉलर, फरवरी में 61.22 और मार्च में 64.73 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था पर पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर रही थी। हालांकि, कई बार ऐसा भी हुआ है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है पर कंपनियों ने इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया। अप्रैल 2020 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत मार्च के मुकाबले करीब 15 डॉलर गिर कर 19.90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। इसके बाद मई में बढकर 30 डॉलर के आसपार पहुंच गई पर कंपनियों ने कच्चा तेल सस्ता होने पर भी कीमत कम नहीं की। 16 मार्च 2020 को पेट्रोल 69.59 रुपए और डीजल 62.29 रुपए प्रति लीटर था।

एल्युमीनियम कबाड़ पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मांग

नयी दिल्ली। एजेंसी

एल्युमीनियम उद्योग ने सरकार से एल्युमीनियम कबाड़ पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मांग की है। भारतीय एल्युमीनियम संघ (एएआई) ने मंगलवार को कहा कि पर्याप्त घरेलू एल्युमीनियम कबाड़ उत्पन्न करने की क्षमता होने के बावजूद भारत में कबाड़ की खपत लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। प्राथमिक एल्युमीनियम पर वर्तमान में 7.5 फीसदी, डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम पर 7.5 से 10 प्रतिशत और एल्युमीनियम स्क्रैप या कबाड़ पर सिर्फ 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क है। संगठन ने एक बयान में कहा, ''यही कारण है कि प्राथमिक एल्युमीनियम क्षमता की महत्वपूर्ण उपस्थिति और पर्याप्त घरेलू कबाड़ उत्पन्न करने की क्षमता होने के बावजूद देश में एल्युमीनियम कबाड़ की खपत 100 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। इसलिए एल्युमीनियम कबाड़ पर सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर देना चाहिए।''

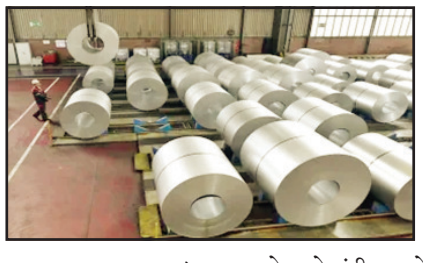

एल्युमीनियम और एल्युमीनियम कबाड़ पर मूल सीमा शुल्क अन्य अलौह धातुओं जैसे जस्ता, सीसा, निकेल और टिन के अनुरूप नहीं है। यह घरेलू एल्युमीनियम उत्पादकों के लिए एक बड़ा नुकसान है। उद्योग को इसके अलावा मूल सीमा शुल्क की दर या अधिकतम सीमा शुल्क दर मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की उम्मीद है। उद्योग के अनुसार, एल्युमीनियम कबाड़ के बढ़ते आयात से प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कुल आयात में एल्युमीनियम कबाड़ की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015-16 में 52 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-22 में 66 प्रतिशत हो गई। इसके कारण 15,000 करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है।

सीआईआई का ईवी वाहनों की चार्जिंग के लिए सेवा शुल्क की सीमा को खत्म करने का सुझाव

नयी दिल्ली। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बिजलीचालित वाहनों (ईवी) की चार्जिंग के लिए सेवा शुल्क की सीमा को खत्म करने का सुझाव दिया है। उद्योग मंडल ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि लागत की अनिश्चितता और प्रयोग के स्तर के हिसाब से फिलहाल शुल्क की कोई भी सीमा निजी निवेश को हतोत्साहित करेगी। सीआईआई ने रसायन सेल बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) पर केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए सरकारी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने का आह्वान किया है। उद्योग मंडल का कहना है कि पीएलआई के तहत शुरुआती 50 गीगावॉट घंटा की क्षमता बड़े बाजार आकार के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। सीआईआई ने अपनी रिपोर्ट में इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क का लाभ उठाने के लिए अंतिम उपयोगकर्ता पर जीएसटी की छूट की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में अलग से बेची गई बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन में लगी हुई आई बैटरी पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

भारत में होने वाली है इन 'स्वदेशी' कारों की एंट्री

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में स्वदेशी कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए हाल ही में ह्यूंदै को पीछे छोड़ दिया है। यह ऑटोमोबाइल बाजार में एक बड़ा उलटफेर था और अब कंपनी अपने फुटहोल्ड को और मजबूत करने के लिए कई नए मॉडल्स बाजार में उतारेगी और भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन और मजबूत करेगी।

1. टाटा नेक्सॉन
2. टाटा सफारी पेट्रोल
3. टाटा हैरियर पेट्रोल
4. टाटा पंच सीएनजी/टर्बो पेट्रोल/डीजल
5. टाटा कूप एसयूवी
6. न्यू जेन टाटा नेक्सॉन
7. टाटा मिड साइज एसयूवी
8. टाटा सिएरा ईवी

बीते कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने भारत में हर सेगमेंट में अच्छी कारें पेश की हैं। खासकर एसयूवी सेगमेंट में हालिया लॉन्च छोटी एसयूवी टाटा पंच के साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन और टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक ने टाटा की किस्मत ही बदल दी और इसी का परिणाम है कि टाटा दिसंबर 2021 महीने में ह्यूंदै से भी ज्यादा कारें बेचने में सफल रही। कंपनी की आगे भी कोशिश रहे कि वह देश की दूसरी सबसे बड़ी कार के रूप में लंबे समय तक अपनी पहचान कायम रखे। कंपनी ने सीएनजी सेगमेंट में भी बीते बुधवार ही एंटर किया है। मारुति और ह्यूंदै को टक्कर देने के लिए कंपनी ने 2 सीएनजी मॉडल बाजार में उतारे हैं। आने वाले समय में भी कंपनी नए सीएनजी मॉडल्स लॉन्च करेगी।

बजट से पहले आता है इकनॉमिक सर्वे, क्यों है यह इतना जरूरी डॉक्यूमेंट? यहां जानिए डिटेल्स से

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2022-23 का बजट अगले महीने के पहले दिन पेश करेंगी। आमतौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में इकनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, हालांकि पिछले साल इसे 29 जनवरी को पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण (इकनॉमिक सर्वे) कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश की जाती है और पूरा लेखा-जोखा रहता है। यह बजट का मुख्य आधार है।

देश की सेहत का लेखा-जोखा है इकोनॉमिक सर्वे

इकनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा होता है। इसके जरिए सरकार देश को अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में बताती है। इसमें साल भर में विकास का क्या ट्रेंड रहा, किस क्षेत्र में कितनी पूंजी आई, विभिन्न योजनाएं किस तरह लागू हुईं इत्यादि इन सभी बातों की जानकारी होती है। इसमें सरकारी नीतियों की जानकारी होती है।

बजट का मुख्य आधार है आर्थिक सर्वे

आर्थिक सर्वे को बजट का मुख्य आधार माना जाता है। हालांकि इसकी सिफारिशें सरकार लागू ही करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसमें सरकारी नीतियों, प्रमुख आर्थिक आंकड़े और क्षेत्रवार आर्थिक रूझानों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। इसे दो हिस्सों में पेश किया जाता है. पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था की हालत बताई जाती है और दूसरे हिस्से में प्रमुख आंकड़े होते हैं।

कोरोना की तीसरी लहर के बीच पेश होगा आम बजट

अगले वित्त वर्ष 2022-23 का बजट ऐसे समय में पेश होने वाला है, जब देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इकनॉमी पर निगेटिव असर दिख रहा है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की चौथा बजट होगा जिसमें कोरोना के झटकों से इकनॉमी को उबारने के उपाय किए जा सकते हैं।

फोर्ब्स लिस्टः अडानी भारत के सबसे बड़े रईस, पांच मिनट के लिए अंबानी से आगे निकले

नई दिल्ली। एजेंसी

अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने संपत्ति के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार को फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अंडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। हालांकि, अडानी करीब पांच मिनट ही देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। बीते पांच सत्रों से घरेलू शेयर बाजारों में मंदी का माहौल था। इसका असर कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर भी पड़ रहा था। बीते दो दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी गिरावट रही। इस कारण मुकेश अंबानी की संपत्ति में भी कमी आई। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रिलायंस के शेयरों में 3 फीसदी तक की गिरावट रही। इससे मुकेश अंबानी की संपत्ति और घट गई। इस कारण मुकेश अंबानी कुल संपत्ति के मामले में गौतम अडानी से पिछड़ गए। हालांकि, थोड़ी देर बाद रिलायंस के शेयरों में तेजी आई और मुकेश अंबानी फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दिनभर के कारोबार के बाद रिलायंस का शेयर 0.16 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 2373.70 रुपए पर बंद हुए।

7 हजार करोड़ रुपए आगे मुकेश अंबानी

फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 91.3 अरब डॉलर यानी करीब 6.82 लाख करोड़ रुपए है। वहीं, गौतम अडानी की कुल संपत्ति 90.3 अरब डॉलर यानी करीब 6.75 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी से करीब 7 हजार करोड़ रुपए आगे हैं।

सरकार ने मानव बालों के निर्यात पर 'अंकुश' लगाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मंगलवार को मानव बाल के निर्यात पर 'अंकुश' लगा दिए हैं। बाल उद्योग के अनुसार, यह एक ऐसा कदम है जिससे इस उत्पाद की भारत से कथित तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। बालों के निर्यात की पहले बिना किसी अंकुश के अनुमति दी गई थी। लेकिन अब एक निर्यातक को वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुमति या लाइसेंस लेना होगा।

विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने एक अधिसूचना में कहा, ''मानव बाल की निर्यात नीति, चाहे उसको लेकर कोई काम न भी किया गया, चाहे उसे धोया गया हो या नहीं धोया गया हो, मानव बाल या किसी अन्य प्रकार के कच्चे मानव बाल ... को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।''

इस पहल का स्वागत करते हुए भारतीय बाल एवं बाल उत्पाद विनिर्माण एवं निर्यातक संघ के सदस्य सुनील ईमानी ने कहा कि यह उनकी लंबे समय से लंबित मांग थी। उन्होंने बार-बार आरोप लगाया है कि यह श्रम प्रधान उद्योग म्यामां और चीन जैसे देशों में कच्चे मानव बाल की तस्करी की एक अजीबोगरीब चुनौती का सामना कर रहा है, जिससे स्थानीय उद्योगों और निर्यात को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, ''अब इस प्रतिबंध के साथ, केवल वास्तविक निर्यातक ही उत्पाद का निर्यात कर पाएंगे।' भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलावा पश्चिम बंगाल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भारत के प्रमुख प्रतियोगी चीन, कंबोडिया, वियतनाम और म्यामां हैं। कच्चे मानव बाल मुख्य रूप से इन राज्यों के घरों और मंदिरों से एकत्र किए जाते हैं और ये मुख्य रूप से विश्वस्तर पर सौंदर्य बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। भारत में दो तरह के बाल एकत्र किए जाते हैं- रेमी और नॉन-रेमी बाल। रेमी बाल, सबसे अच्छा ग्रेड, मंदिरों से एकत्र किया जाता है जहां तीर्थयात्री धार्मिक व्रत के हिस्से के रूप में अपने बाल दान करते हैं। इस गुणवत्ता वाले बाल का उपयोग मुख्य रूप से हेयरपीस और विग बनाने के लिए किया जाता है। गैर-रेमी बाल गांवों और शहरों में लोगों के छोटे समूहों द्वारा एकत्र किया जाने वाला घरेलू कचरा है। वे उसे अलग करते हैं और डीलरों को बेचते हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान बालों का निर्यात 14.42 लाख डॉलर रहा है, जबकि वर्ष 2020-21 में यह सिर्फ 1.52 करोड़ डॉलर रहा था।

देश में पहली बार एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और लुब्रिकेंट का ट्रायल शुरू

फरीदाबाद। एजेंसी

डीजल से चलने वाले वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर, कैडमियम तथा नाइट्रोजन के आक्साइड पर्यावरण प्रदूषित करने का बड़ा कारण बनते हैं। इंडियन आयल अनुसंधान केंद्र ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और कांबो लुब्रिकेंट के रूप में अपने नए अनुसंधान से देशभर में वायु प्रदूषण को कम करने की उम्मीद जगाई है। अनुसंधान केंद्र ने शनिवार को देश में पहली बार हरियाणा रोडवेज की 20 बसों में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल डाल कर ट्रायल के रूप में इसकी शुरुआत कर दी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल से चलने वाली बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 40 हजार किलोमीटर का ट्रायल पूरा होने के बाद पूरे प्रदेश की हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रयोग किया जाएगा।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कहा कि एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और कांबो लुब्रिकेंट का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सपनों को साकार करेगा। इंडियन आयल ने राष्ट्र हित में बेहतरीन कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूटन यानी नेट जीरो कार्बन इकनामी का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर इंडियन आयल के अधिकारी डा.दीपक सक्सेना, गंगाशंकर मिश्र, मुकुल महेश्वरी, महाप्रबंधक डा.पंकज भटनागर, सहायक प्रबंधक एचआर कमेलश गुप्ता मौजूद थे। इंडियन आयल के आरडी सेंटर के निदेशक डा.एसएसबी रामा कुमार ने बताया कि चूंकि उनका अनुसंधान केंद्र फरीदाबाद में ही है, इसलिए अपने शहर को ट्रायल केंद्र के रूप में चुनना बेहतर है।

क्या है एक्सट्रा ग्रीन डीजल

इंडियन आयल के आरडी सेंटर के निदेशक डा.एसएसबी रामाकुमार के अनुसार आम डीजल क्रूड आयल से बनता है। एक्सट्रा ग्रीन डीजल में हमने अपने अनुसंधान केंद्र में विकसित किए गए इनोवेटिव केमिकल सब्सेंट्स रासायनिक पदार्थ का मिश्रण किया है। इसमें कोई टाक्सिक नहीं है, कोई मैटेलिक कंटेंट नहीं हैं। आम डीजल के प्रयोग से इंजन में कार्बन जम जाता है, जबकि ग्रीन डीजल कार्बन को साफ करने में मदद करेगा। इससे इंजन साफ सुथरा रहेगा, तो प्रदूषण कम होगा। डा.रामाकुमार के अनुसार ग्रीन डीजल के प्रयोग से 20 प्रतिशत प्रदूषण की कमी आएगी। इससे इंजन की क्षमता भी बढ़ेगी और माइलेज भी बढ़ेगा। एक लीटर आम डीजल में कोई गाड़ी अगर 15 किलोमीटर चलती है, तो ग्रीन डीजल से पांच प्रतिशत ज्यादा चलेगी। इस तरह पर्यावरण को भी फायदा होगा और गाड़ी मालिक का खर्च भी कम होगा। ग्रीन डीजल की कीमत कम या ज्यादा के सवाल पर डा.रामाकुमार ने कहा कि आम डीजल से इसकी कीमत मामूली रूप से ज्यादा होगी। उन्होंने बताया कि ट्रायल पूरा होने के बाद इसके परिणाम पर नजर डाली जाएगी और उसके बाद बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक में हमारी देश के विभिन्न जिलों में स्थित रिफाइनरी से उपलब्धता सुनिश्चित करने को हरी झंडी मिलेगी। फरीदाबाद में रहता है सर्वाधिक प्रदूषण

औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में एक-दो महीने को छोड़कर बाकी महीने आमजन साफ हवा को तरसते रहते हैं। इस साल वायु

उद्योग जगत की ये नामचीन हस्तियां शामिल हैं पद्म सम्मान की सूची में, जानिए उनका योगदान

नयी दिल्ली। एजेंसी

एन चंद्रशेखरन, कृष्णा इल्ला, सुचित्रा इल्ला, साइरस पूनावाला, सुदर पिचाई आदि को तो आप जानते ही होंगे। हालांकि, ये अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन इनमें एक समानता है। इन सबको पद्म सम्मान देने की घोषणा हुई है। इन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के बदले इससे सम्मानित किया गया है।

कौन हैं कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला

भारत बायोटेक की सफलता के पीछे उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कृष्णा इल्ला और उनकी पत्नी तथा सह-संस्थापक और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा इल्ला रही हैं। इन्हें पद्म भूषण सम्माना दिया गया है। इन्हीं की कंपनी ने स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सिन विकसित किया। आणविक जीव विज्ञान में शोध वैज्ञानिक, कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला ने 1996 में भारत बायोटेक की स्थापना की थी। आज, भारत बायोटेक अभिनव टीकों के उत्पादन के मामले में दुनिया की प्रमुख कंपनी है।

साइरस एस पूनावाला

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एष्ठ) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साइरस एस पूनावाला हैं। उन्हें भी पद्म भूषण सम्मान मिला है। उनकी कंपनी दुनिया भर में उत्पादित और बेची जाने वाली खुराक की संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन विनिर्माता है (1.5 बिलियन से अधिक खुराक)। इसमें पोलियो वैक्सीन के साथ-साथ डिप्थीरिया, टेटनस, बीसीजी आदि के टीके शामिल हैं। ऐसा अनुमान है कि दुनिया में लगभग 65 प्रतिशत बच्चों को पुणे स्थित कंपनी में बना कम- से- कम एक टीका जरूर लगा है।

टाटा ग्रुप के चंद्रशेखरन

टाटा समूह की कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और प्रवर्तक टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (Natarajan Chandrasekaran) को भी पद्मभूषण सम्मान दिया गया है। चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के 110 अरब डॉलर से अधिक के कुल सालाना राजस्व वाले समूह की अगुवाई कर रहे हैं। वह टाटा संस के निदेशक मंडल से अक्टूबर, 2016 में जुड़े और जनवरी, 2017 में चेयरमैन नियुक्त किये गये। इससे पहले, वह वैश्विक आईटी समाधान और परामर्श कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से 30 साल से जुड़े थे।

सत्य नडेला

वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्य नडेला पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं। वह वर्ष 1992 में कंपनी में शामिल हुए थे। फरवरी, 2014 में सीईओ बनाये जाने से पहले, उन्होंने कंपनी में उद्यम और उपभोक्ता व्यवसायों दोनों में नेतृत्व स्तर पर भूमिका निभाई। मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले नडेला ने मेंगलूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की।

सुदंर पिचाई

अल्फाबेट इंक और इसकी सहायक कंपनी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वह 2004 में गूगल में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कंपनी के कई उत्पादों के लिए उत्पाद प्रबंधन और नवोन्मेषी प्रयासों का नेतृत्व किया था। अगस्त, 2015 में उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया।

पद्म श्री से सम्मानित हुए हैं ये

व्यापार और उद्योग जगत से पद्म श्री सम्मान हासिल करने वालों में रूपा एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष प्रहलाद राय अग्रवाल, चंडीगढ़ स्थित जगजीत सिंह दर्दी और गुजरात के सावजी ढोलकिय भी शामिल हैं।।

पद्म पुरस्कार का महत्व

पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार विभिन्न विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों, जैसे- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, आदि- में योगदान के लिए दिए जाते हैं।

तनाव के बीच व्यापार चीन से भारत का आयात 100 अरब डॉलर पहुंचा

स्मार्टफोन और मशीनरी में भारी उछाल

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत और चीन के बीच रिश्तों के उतार-चढ़ाव की खबरें आती रहती हैं। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते व्यापार क्षेत्र में और गहरे हो रहे हैं। कैलेंडर वर्ष 2021 में पहली बार चीन से भारत में आयात लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, विशेष रूप से स्मार्टफोन, मशीनरी, उर्वरक, विशेष रसायनों और सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के आयात में भारी उछाल देखा गया है। चीन के कस्टम विभाग (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत को होने वाला निर्यात 97.52 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया जबकि कुल दोतरफा द्विपक्षीय व्यापार 125.66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

इन सामानों का सबसे ज्यादा व्यापार

जीएसीसी के अनुसार, स्मार्टफोन और स्टोरेज इकाइयों सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के शिपमेंट में सबसे बड़ी उछाल देखी गई है। इन सामानों में टेलिकॉम उपकरण, ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल, विशेष रसायन, यूरिया, अमोनिया सल्फेट और अन्य किस्मों जैसे उर्वरक शामिल हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार प्रदर्शन विश्लेषण के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के पहले आठ महीनों में चीन से प्रमुख आयात वस्तुओं में, पेट्रोलियम (कच्चा) और पेट्रोलियम उत्पादों, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के साथ-साथ कोयला, कोक और ब्रिकेट्स के आयात में भारी वृद्धि देखने को मिली। इस अवधि के दौरान चीन से कुल आयात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 60 अरब डॉलर है। दिसंबर के लिए कमोडिटी-वार डेटा भारत द्वारा जारी किया जाना बाकी है।

चीन पर भारत की निर्भरता और बढ़ सकती है

एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेएनयू में व्यापार अर्थशास्त्री और प्रोफेसर बिस्वजीत धर ने बताया कि चीन के साथ भारत के समग्र संबंध अमेरिका-चीन संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का अलग आधार है। आगे उन्होंने कहा कि चीन के साथ अपने बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के बावजूद, अमेरिका 'दुनिया के कारखाने' पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पाया है। भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत भी चीनी अर्थव्यवस्था से अलग होने में असमर्थ रहा है। साथ ही कहा कि जब हमारे उद्योग पूरी तरह महामारी से उबर जाएंगे तो चीन पर भारत की निर्भरता और बढ़ सकती है।

वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 चीन-भारत व्यापार 125 बिलियन डॉलर के पार हो गया है, यह एक रिकॉर्ड स्तर है। और दोनों देशों के तनाव के बीच यह इस बात का प्रमाण है कि भारत चीनी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करने में असमर्थ है। वहीं अर्थशास्त्री अजीत रानाडे ने कहा कि चीन से एपीआई के आयात पर भारत की निर्भरता को दूर करने में भी लंबा समय लगेगा।

चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में रत्न एवं आभूषण निर्यात 71 प्रतिशत बढ़कर 28.9 अरब डॉलर पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश से रत्न एवं आभूषणों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान 71 प्रतिशत बढ़कर 28.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में रत्न एवं आभूषण निर्यात 16.9 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2021 में रत्न एवं आभूषण निर्यात 16.38 प्रतिशत बढ़कर 2.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया। समीक्षाधीन अवधि में देश के कुल निर्यात में क्षेत्र की हिस्सेदारी 9.6 प्रतिशत रही। रत्न एवं आभूषण निर्यात के पांच प्रमुख गंतव्यों में अमेरिका, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम और इस्राइल शामिल हैं। यह उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब सात प्रतिशत का योगदान देता है। इस क्षेत्र में 50 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।

UNION BUDGET 2022

बजट 2022 से हैं ये 22 बड़ी उम्मीदें यहां जानें किस सेक्टर ने उठाई क्या मांग

देश का आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट देश के सामने रखेंगी। यह मोदी सरकार का 10वां बजट होगा। बीते वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का एलान किया जा सकता है। यहां हम बजट 2022 से जुड़ी 22 उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं।

1 स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में इजाफा

बजट 2022 से वेतन भोगियो को इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल, इनके लिए इस समय धारा 16 के तहद स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपये निर्धारित है। लंबे समय से इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है। वेतन भोगियों को उम्मीद है की इसको बढ़ाया जाए। इसे बढ़ाए जाने से वेतन भोगियो को सीधा-सीधा कर लाभ होगा।

2 वर्क फ्रॉम होम अलाउंस टैक्स छूट

कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे है। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर आदि पर खर्चा बढ़ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी वर्क प्रॉम होम के तहत घर से काम करने वालों को अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव दिया है।

इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और 80सी में छूट

3 कोरोना के चलते बीते दो साल में हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस बढ़ा है। बजट 2022 से उम्मीदें है कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी से बाहर किया जा सकता है और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई एक लिमिट बढ़ाई जा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है या फिर 80सी की लिमिट का ओवरआल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर लगभग ज्यादातर करदाताओं को बड़ा फायदा होगा।

4 इंश्योरेंस पर जीएसटी से राहत

बजट में सरकार का ज्यादा जोर देश के करदाताओं पर रहने की संभावना है क्योंकि पिछले कई बजट में करदाताओं के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है। इस बार के बजट में इंश्योरेंस/मेडिक्लेम प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी कम करने की उम्मीद भी करदाताओं को है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस मांग को सरकार की ओर से बजट 2022 में शामिल किया जा सकता है। टाटा कैपिटल में वेल्थ मैनेजमेंट के प्रमुख सौरव बसु महामारी ने बीमा को बहुत महत्व दिया है और हमें उम्मीद है कि सरकार बीमा प्रीमियम पर लगाए जा रहे 18 फीसदी जीएसटी को कम करेगी, ताकि कवर की कुल लागत आबादी के लिए वहनीय बनी रहे। पॉलिसी प्रीमियम पर 5 फीसदी का जीएसटी अधिक लोगों को बीमा योजनाओं को चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस पर राय व्यक्त करते हुए इफ्ब्पिंटू सीईओ दर्पण सैनी ने कहा कि सरकार को डिजिटल हेल्थकेयर को किफायती बनाने की जरूरत है। प्रीमियम पर जीएसटी 5 फीसदी करके स्वास्थ्य बीमा को वहनीय बनाने पर विशेष ध्यान देना एक व्यवहार्य विकल्प है।

5 फिनटेक को कर राहत की आस

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों (फिनटेक) को इस साल बजट में कर राहत मिलने की उम्मीद है। कंपनियों का कहना है कि तरलता प्रवाह बढ़ाने के उपाय, खुदरा क्षेत्र में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए कम लागत वाली फंडिंग के साथ-साथ जीएसटी और टीडीएस पर छूट की शुरुआत बजट में होनी चाहिए। फाइनेंसपीयर के संस्थापक और सीईओ रोहित गजभिये, ने कहा कि फिनटेक क्षेत्र 2021 के लिए एक रोमांचक रहा है, जिसमें उद्योग ने रिकॉर्ड उच्च निवेश आकर्षित किया है।फिनटेक और एनबीएफसी क्षेत्र ने ग्रामीण बाजारों में गहरी पैठ बनाई है, जहां बैंकिंग सेवाएं एक चुनौती थीं। बजट 2022 को अनुकूल नीतियों और प्रतिबंधों में ढील देकर फिनटेक उद्योग की वृद्धि और सफलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक मजबूत डाटा सुरक्षा तंत्र के बिना फलता-फूलता डिजिटल बुनियादी ढांचा पूरा नहीं होगा। इस केंद्रीय बजट में डेटा सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

6 ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मिलेगी राहत

घरेलू आटोमोबाइल सेक्टर पिछले दो दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश के कुल जीडीपी में आटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7.5 प्रतिशत है, जबकि यह प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र को नए निवेश के लिए तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहन चाहिए। खास तौर पर आटोमोबाइल सेक्टर में एक समान टैक्स लगाने की व्यवस्था भी लागू करने की मांग हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ईवीएस के पक्ष में है। ऑनलाइन कार खरीद-बिक्री प्लेटफॉर्म ड्रूम टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सीईओ एमआर संदीप अग्रवाल ने कहा कि पिछले 2 दशकों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जबरदस्त विकास और परिवर्तन हुआ है।

कोविड के बाद, हमने देखा है कि भौतिक संपर्क से बचने के कारण ऑटोमोबाइल खरीद और बिक्री तेज गति से ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के नियमों का डिजिटलीकरण जारी रहेगा। हमें उम्मीद है कि सरकार ईवी मांग को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी।

7 डिजिटल इंडिया को बढ़ावा

विशेषज्ञों के अनुसार, अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान शानदार ग्रोथ नजर आई है और देश फिर से विकास की राह पर अग्रसर है। अगर सरकार रिफॉर्म बनाए रखती है तो इससे 2022 में भी रिकवरी तेज होगी और इकोनॉमी बूस्टर का टेम्पो बना रहेगा। स्टार्टअप गतिविधियों और सरकार के राहत पैकेज से भारत में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने, कर संरचना को सरल बनाने और लैंड-लेबर लॉ में सुधार से ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में सरकार इन उम्मीदों को कायम रखने का काम करेगी।

8 प्रोत्साहन पैकेजों की उम्मीद

गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी। ऐसे में इस बार भी देश की अर्थव्यस्था पर कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन वैरिएंट का साया है तो उम्मीद है कि इस बार भी कुछ बड़े प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की जा सकती है।

9 रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बूस्ट

इस साल का केंद्रीय बजट टैक्स और वेवर में कुछ प्रमुख छूट, रॉ मैटेरियल पर जीएसटी में कटौती की पेशकश करके रीयल एस्टेट क्षेत्र में सहायक भूमिका निभा सकता है। चूंकि यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, इस क्षेत्र को मजबूत करने से संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। विशेषज्ञों की मानें तो लोगों ने कोविड के बाद के दौर में घर खरीदने के महत्व को महसूस किया है। जबकि सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में कटौती, सबसे कम होम लोन दरों जैसे कुछ लाभ दिए है और समर्थन किया है। आगामी बजट को रीयल एस्टेट क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखना चाहिए क्योंकि यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

10 कोरोना मरीजों-उनके परिवार को राहत

कोरोना महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गया तो कई की आय बिल्कुल कम हो गई। ऐसे में आम लोग बजट 2022 को उम्मीदों से देख रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान कई कोरोना मरीजों व उनके परिवारों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों, दोस्तों व समाज सेवकों से वित्तीय सहायता मिली लेकिन बहुत से लोगों को यह पूरी लड़ाई अपने बूते लड़नी पड़ी। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लोगों को कोरोना के इलाज पर हुए खर्च पर डिडक्शन का फायदा देने पर सरकार विचार कर सकती है।

11 ज्वेलरी उद्योग ने सामने रखी मांगें

आगामी 1 फरवरी को देश का जो आम बजट पेश किया जाएगा। उससे देश के करदाताओं समेत सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। ज्वेलरी सेक्टर ने भी अपनी मांग सामने रखी हैं। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंह सिंघल का कहना है कि इनकम टैक्स के 3 स्लैब रेट 10ज्ञ /15%/20ज्ञ से ऊपर नहीं होने चाहिए। सोना, चांदी, हीरा की खरीद बिक्री के लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से घटाकर 10% व शोर्ट टर्म 30% से घटाकर 20% होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि क्रेडिट कार्ड पर कोई बैंक चार्ज नहीं लगना चाहिए, जीएसटी सेल्स टैक्स की तरह 1% होना चाहिए और सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी 4% होनी चाहिए। इससे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।

12 एमएसएमई को बजट से बड़ी उम्मीदें

कोरोना से सबसे प्रभावित एमएसएमई सेक्टर की मांग है कि जीएसटी की दरों को इस सेक्टर के लिए उपयुक्त बनाया जाए और इस सेक्टर के लिए टैक्स की दरों को कम किया जाए। उत्पादन में गिरावट, नौकरियों में कमी, राजस्व में कटौती जैसी कई समस्याओं का सामना एमएसएमई सेक्टर को पिछले दो सालों में करना पड़ा है। ऐसे में एमएसएमई की सबसे बड़ी मांग है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की दरों पर एक बार फिर विचार किया जाना चाहिए। हैबनेरो फूड्स के संस्थापक और एमडी ग्रिफ़िथ डेविड ने कहा कि पिछले एक साल में, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई पहल की हैं। एमएसएमई एक आत्मानिर्भर भारत की नींव प्रदान करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का दिल हैं। यह सुनिश्चित करने के साथ कि एमएसएमई को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले, हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को लागू करेगी।

इनकम टैक्स के 80डी सेक्शन में बदलाव

13 आपको बता दें कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार रुपये तक के डिडक्शन का लाभ दिया जाता है। हालांकि यह फायदा उन्हें तभी मिलता है, जब वह किसी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं हैं। इस बार के बजट में विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण के दौरान सेक्शन 80डी के तहत सभी उम्र के लोगों को डिडक्शन का फायदा देने पर विचार कर सकती है। जो उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए खुद के या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर खर्च किया हो।

14 किफायती घर खरीदारों को राहत

सूत्रों का कहना है कि सरकार बजट 2022 में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए बढ़ा सकती है। बता दें, सेक्शन 80ईईए के तहत 45 लाख रुपये तक के मकान पर 1.5 लाख रुपये की होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है।

15 पीपीएफ की सीमा 3 लाख होने की उम्मीद

चार्टड अकाउंटेंट की संस्था आईसीएआई ने भी वित्त मंत्री को अपना सुझाव दिया है। इंस्टीच्युट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट (आईसीएआई) ने वित्त मंत्री को पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश की अधिकत्तम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। आईसीएआई के मुताबिक पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाने से जीडीपी में घरेलू सेविंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हेल्थकेयर क्षेत्र को आवंटन बढ़ने की उम्मीद

16 कोरोना महामारी के इस दौर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुल फंड आवंटन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने की मांग भी उठाई गई है। इस बार विशेषज्ञ कोविड-19 में बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए वेल्थ टैक्स और विरासत कर को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक यश मुथा ने कहा पिछले कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि देखी है। हाल ही में शुरू किया गया आयुष्मान भारत हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सही दिशा में एक बड़ा कदम है। बजट 2022 से स्वास्थ्य क्षेत्र को इस बार भी बड़ी उम्मीद है। उन्होंने कहा चूंकि स्वास्थ्य और समग्र कल्याण (निवारक देखभाल) स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, बजट को स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस प्रकार भारत के ग्रामीण हिस्सों में त्वरित निदान केंद्रों तक पहुंच को सक्षम करना चाहिए।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आस

17 हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र उन सेक्टर में शामिल है जिसपर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस महामारी के प्रकोप का खामियाजा भुगत रहे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बजट 2022 में एक बहाल जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट देख रहा है। वहीं, सेक्टर रेस्टोरेंट व्यवसाय को एक और लॉकडाउन से बचाने के लिए एक सिस्टम चाहता है।

किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात

18 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतंर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अभी 6 हजार रुपये सालाना रकम दी जाती है। वहीं 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में इस राशि को बढ़ाने का एलान हो सकता है। पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया जा सकता है।

शेयर बाजार की ओर से ये मांग

19 स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स की भी बड़ी उम्मीदें बजट पर टिकी हैं। वे प्रतिभूति लेनदेन कर में कमी चाहते हैं। शेयर बाजार से विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) खत्म कर देना चाहिए या इसमें कमी करनी चाहिए।

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संभावना

20 सरकार आगामी आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री को कर के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। कर विशेषज्ञों की मानें तो सरकार इस बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद पर टीडीएस / टीसीएस लगाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लेन-देन को विशेष लेन-देन के दायरे में लाया जाना चाहिए।

विमानन उद्योग कर रहा ये उम्मीद

21 विमानन उद्योग कम से कम 2 वर्षों के लिए कर छूट और न्यूनतम वैकल्पिक कर के निलंबन की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा, महामारी प्रभावित एयरलाइंस भी न्यूनतम वैकल्पिक कर को निलंबित करना चाहती हैं। कोरोना महामारी ने विमानन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।

एफएमसीजी क्षेत्र ने जताई यह इच्छा

22 एफएमसीजी क्षेत्र की इच्छा है कि सीतारमण लोगों के हाथों में पैसा देना जारी रखें, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की ओर से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव भेजे गए हैं। क्षेत्र को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस ओर विशेष ध्यान देंगी।

बजट की प्रथा कब-कहां हुई शुरू और ये भारत कैसे आई, यहां जानें इसके इतिहास से जुड़ी जरूरी जानकारियां

देश का आम बजट यानी देश का वित्तीय लेखा-जोखा। भारत में हर साल बजट एक फरवरी को पेश होता है और बजट 2022 पेश होने में महज हफ्तेभर का समय बाकी रह गया है। लेकिन क्या आप बजट के इतिहास के बारे में जानते हैं। हम आपको बजट शब्द की उत्पत्ति से लेकर ये प्रथा कहां से शुरू हुई, भारत कब आई जैसी तमाम अहम सवालों के जवाब दे रहे हैं।

ऐसे हुई बजट शब्द की उत्पत्ति

बजट शब्द की उत्पति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट की उत्पति हुई। इसके बाद अंग्रजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था।

1850 के दशक से शुरू हुई बजट प्रथा

बजट की प्रथा 1850 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई जब विलियम ग्लैडस्टोन 1852 से 55 तक राजकोष के चांसलर थे। ग्लेडस्टोन बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ब्रिटेन में इस प्रथा को हिन्दुस्तानी शब्द बजट पर्दा के रूप में जाना गया। ग्लैडस्टोन के वक्त से ही यह एक नियमित प्रथा बन गई कि चांसलर के बजट पढ़ने से पहले उसका कोई हिस्सा लीक नहीं हो।

ब्रिटिश काल में पेश हुआ भारत का पहला बजट

आम बजट दरअसल, सरकार की ओर से दिया जाने वाला सालभर के लिए देश की आय और खर्च का लेखा-जोखा होता है। इसे पेश करने की शुरुआत ब्रिटेन द्वारा की गई थी। ब्रिटिश काल में पहली बार भारत में 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया था। इस बजट को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था।

11 बजे ही क्यों पेश होता है बजट?

बजट अब सुबह 11 बजे पेश किया जाता है, हालांकि ऐसा पहले से नहीं चल रहा। इससे पहले ब्रिटिश काल में बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, ऐसा इसलिए किया जाता था, ताकि रात भर बजट पर काम करने वाले अधिकारियों को थोड़ा आराम मिल सके। यही नहीं 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, लेकिन 1955-56 से सरकार ने इसे हिंदी में भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया। 1999 में बजट पेश करने के समय को बदलकर सुबह 11 बजे किया गया।

चमड़े का लाल बैग में आता था बजट

ब्रिटिश काल में जब वित्त मंत्री संसद में सरकार का खर्च और आय की जानकारी देते थे और इसे चमड़े के लाल बैग में लेकर आया जाता था। इसके नाम से जुड़े तत्यों के चलते ऐसा होता था और यहीं परंपरा निरंतर जारी रही। लेकिन भाजपा सरकार ने लाल बैग की परंपरा को खत्म किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में चमड़े के ब्रीफकेस के बजाय बही-खाता (पारंपरिक लाल कपड़े में लिपटे कागज) में बजट दस्तावेजों को ले जाने की प्रथा शुरू की।

स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट

स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया यह सवाल लगभग सभी के मन में रहता है। तो जा लें कि भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षण्मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। बता दें कि चेट्टी का जन्म 1892 में हुआ था। वे एक वकील, राजनेता, और अर्थशास्त्री थे।

ये वित्त मंत्री नहीं कर सके बजट पेश

केसी नियोगी भारत के अकेले ऐसे वित्त मंत्री रहे, जिन्होंने इस पद पर रहते हुए भी एक भी बजट पेश नहीं किया। दरअसल, वे 35 दिनों तक 1948 में वित्त मंत्री रहे थे। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जान मथाई ने पेश किया था।

गरीबों के हाथों में अधिक पैसा देने की जरूरत

दुकान-सैलून वालों के लिए ECLGS की घोषणा करे सरकार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अगले हफ्ते बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। खुदरा विक्रेताओं के संगठन रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने सरकार से रिटेल सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की जरूरत पर सुझाव दिया है। आरएआई का कहना है कि कोरोना वायरस से प्रभावित क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जरूरत है। आरएआई ने अपनी बजट इच्छा लिस्ट में कहा कि गरीबों के हाथों में अधिक पैसा देने की जरूरत है। दो साल में महामारी ने गरीब वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है।

आरएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कुमार राजगोपालन ने एक बयान में कहा, कोरोना से संबंधित प्रतिबंध सबसे अधिक रेस्तरां, दुकानों, सैलून आदि जैसे हाई कॉन्टैक्स सेक्टर्स को प्रभावित करते हैं। इसलिए खुदरा क्षेत्र में फाइनेंस के लिए ईसीएलजीएस की घोषणा की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, हालांकि, खुदरा क्षेत्र को हाल में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (MSME) के तहत प्राथमिकता क्षेत्र लेंडिंग दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है, लेकिन यह जरूरी है कि उसे एमएमएसई नीतियों के तहत मिलने वाला समर्थन दिया जाए, क्योंकि 90 प्रतिशत खुदरा क्षेत्र को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

ONDC के जरिए रिटेल सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है

उन्होंने कहा, डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी खुदरा क्षेत्र को बेहतर ढंग से बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इसके अलावा डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के जरिये खुदरा विक्रेताओं को सक्षम कर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के लिए बेहतर दिशानिर्देशों की मांग करते हुए संघ ने कहा कि कपड़ों, भोजन और हाउसिंलग पर जीएसटी की दरों में कोई भी बढ़ोतरी खपत पर सीधा प्रभाव डालती है। अधिक अनुमानित जीएसटी व्यवस्था के लिए एक दिशा का स्वागत किया जाएगा। इसी तरह, जीएसटी को आगे ले जाने और रिफंड के लिए कई क्लॉज स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। राजगोपालन ने कहा कि खुदरा और आंतरिक व्यापार के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय नीति के निर्माण के लिए दिशात्मक समर्थन से मदद मिलेगी।

गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के हाथों में हो अधिक पैसा

गरीबों और वेतनभोगियों के हाथों में अधिक पैसा मांगते हुए आरएआई ने कहा कि दो साल के कोरोना वायरस महामारी ने गरीब वर्ग आबादी के कई लोगों को प्रभावित किया है। राजगोपालन ने कहा, रिवर्स माइग्रेशन और लॉकडाउन के कारण कई लोग बिना नौकरी के थे। कोई भी योजना जो गरीबों की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है, उसका स्वागत किया जाएगा। इसी तरह, वेतनभोगी वर्ग को भी अपने हाथों में अधिक धन प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें विश्वास के साथ उपभोग करने में मदद मिल सके। बढ़ती महंगाई चिंता का विषय है और उपभोक्ता वर्ग के पास ज्यादा पैसा होने पर ही इसका बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है।

ग्रहों का अद्भुत संयोगः फरवरी में मकर राशि में एक साथ रहेंगे पांच ग्रह, सर्दी का असर होगा कम और बढ़ने लगेगी गर्मी

अगले महीने फरवरी में मकर राशि में ग्रहों का महासंयोग होने वाला है। फरवरी में मकर राशि में त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनेगा। फरवरी में बन रहे ग्रहों के योगों का असर लंबे समय तक दिखाई देगा।

उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के अनुसार फरवरी के अंत में पंचग्रही यानी पांच ग्रहों का योग बनेगा। इसका प्रभाव मार्च में भी दिखेगा। पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इनके नतीजे वाले दिन यानी 10 मार्च को तीन ग्रह शुक्र, मंगल और शनि मकर में रहेंगे। तीन अन्य ग्रह सूर्य, बुध और गुरु कुंभ राशि में रहेंगे। इन ग्रहों की वजह से चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं।

फरवरी में कब बनेंगे कौन से योग

फरवरी में तीन बड़े योग बन रहे हैं। माह के आरंभ में मकर राशि में सूर्य, बुध, चंद्र और शनि ग्रह युति रहेगी। इसके बाद चंद्र जल्दी ही राशि से निकल जाएगा। 13 फरवरी को सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में जाएगा। 26 को मंगल उच्च का होकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस कारण मकर राशि में मंगल, बुध और शनि का योग बनेगा। 28 फरवरी को शुक्र और चंद्र भी मकर में आ जाएंगे, जिससे पंचग्रही योग बनेगा।

मौसम में बदलाव आने लगेगा

ग्रहों के इन योगों की वजह से मौसम में सर्दी का असर कम होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी कम होने लगेगी। फरवरी-मार्च में मौसम सुहाना रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ती जाएगी। दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। समुद्री किनारों में गर्मी ज्यादा रहेगी।

फरवरी में कौन-कौन से शुभ काम करें

फरवरी में सभी 12 राशियों के लोगों को शनि के लिए तेल का दान करना चाहिए। चंद्र और शुक्र के लिए शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। गुरु ग्रह के लिए चने की दाल का दान करें। सूर्य को रोज जल चढ़ाएं। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल का दान करें।

आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर नौ प्रतिशत किया

वाशिंगटन। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ से पहले भी कई एजेंसियां कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन की वजह से कारोबारी गतिविधियों और आवागमन पर पड़ने वाले प्रभाव के चलते अपने वृद्धि दर के अनुमान में कमी कर चुकी हैं।

वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने विश्व आर्थिक परिदृश्य पर अपने ताजा अनुमान में कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इससे पहले आईएमएफ ने पिछले साल अक्टूबर में 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

बीते वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आईएमएफ का ताजा अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के 9.2 प्रतिशत और भारतीय रिजर्व बैंक के 9.5 प्रतिशत के अनुमान से कम है। इसके अलावा यह एसएंडपी के 9.5 प्रतिशत और मूडीज के 9.3 प्रतिशत के अनुमान से भी कम है। हालांकि, यह विश्व बैंक के 8.3 प्रतिशत और फिच के 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान से अधिक है। आईएमएफ ने कहा कि 2023 के लिए भारतीय संभावनाएं ऋण की वृद्धि और उसके साथ निवेश और उपभोग की वृद्धि पर निर्भर हैं।

मुद्रा कोष ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 के 5.9 प्रतिशत से घटकर 2022 में 4.4 प्रतिशत रहेगी। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा है कि महामारी के तीसरे साल में प्रवेश के साथ वैश्विक पुनरुद्धार कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप के तेजी से प्रसार की वजह से कई देशों में आवाजाही पर अंकुश लगाए गए हैं, जिससे श्रमबल का संकट पैदा हो गया है।

प्रसिद्धि पाने के लिए अपनाएं यह उपाय

लोकप्रियता पाने के लिए कई गुणों का होना जरूरी है। समाज में अलग पहचान बनाने के लिए लोग तमाम तरह के प्रयास करते हैं। वास्तु शास्त्र में प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाने से समाज में अलग मुकाम और प्रतिष्ठा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। घर और अपने आसपास की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव लाकर जीवन स्तर को उच्च किया जा सकता है। प्रसिद्धि पाने के लिए प्रतिदिन मां माता दुर्गा की उपासना करें। मां के चरणों में लौंग, चूड़ियां, कपूर, गुड़हल के फुल, सिंदूर और इत्र रखकर मां का ध्यान करें। बुजुर्गों का सम्मान करें। सामाजिक ख्याति प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव की उपासना करें। सूर्यदेव को नमन कर पीला वस्त्र और लाल चंदन का दान करें। सदैव सकारात्मक ऊर्जा से युक्त लोगों के पास रहें। घर से बाहर निकलें तो सिंदूर का टीका लगाकर ही निकलें। श्री राधा-कृष्ण परम सुख के सागर हैं। इसलिए इनके चित्र को घर में लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों का भाग्योदय होता है। सोमवार को घर से बाहर निकलने से पहले शीशे में अपना चेहरा देखकर निकलें। मंगलवार को घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाकर निकलें। बुधवार को हरी धनिया की पत्ती खाकर निकलें। गुरुवार को कोई विशेष कार्य से जाना हो तो घर से निकलने से पहले सरसों के कुछ दाने मुंह में डालकर निकलें। शुक्रवार को दूध से बनी चीजों को सेवन करें। शनिवार को आप किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो घी खाकर निकलें। रविवार को विशेष कार्य से जाना हो तो पान का पत्ता अपने पास रखकर निकलें।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग में छाप छोड़ने के लिए भारत ने कसी कमर, चीन और वियतनाम को यूं देगा टक्कर

नई दिल्ली। एजेंसी

इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में भारत, चीन और वियतनाम को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। लक्ष्य अगले चार वर्षों में 300 अरब डॉलर के उत्पादन का है, जिसमें निर्यात के लिए आरक्षित 120 अरब डॉलर शामिल हैं। इसके अलावा इंसेंटिव्स के लिए उत्पाद-बास्केट का विस्तार करना; आधुनिक सुविधाओं के साथ विशेष रूप से तैयार किए गए बड़े औद्योगिक क्षेत्र; और उन फैक्ट्रियों के लिए अनुमति भी शामिल है, जिनमें डॉर्मिटरीज, किचन, मेडिकल सेट-अप और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के साथ 1 लाख से अधिक कर्मचारी हो सकते हैं।

भारत की योजना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को एक नए लेवल तक ले जाने की है, जो अंततः मजबूत सप्लायर इको-सिस्टम, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर और वैश्विक सर्विसिंग का निर्माण करे। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव और जूनियर मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने 'विजन डॉक्युमेंट 2.0' प्रस्तुत किया है। इसे उनके मंत्रालय ने तैयार किया है और और इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रेजेंट किया गया है।

वैश्विक के साथ-साथ घरेलू कंपनियां भी मैन्युफैक्चरिंग में हों

आगे

वैष्णव का कहना है कि सरकार पहले ही अगले छह वर्षों में चार उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं (सेमीकंडक्टर और डिजाइन; स्मार्टफोन; आईटी हार्डवेयर, और कंपोनेंट्स) में लगभग 17 अरब डॉलर का वादा कर चुकी है। अब सरकार और अधिक श्रेणियां लाएगी, जहां लाभ स्थानीय विनिर्माण के लिए बढ़ाया जाएगा। इनमें हियरेबल्स व वियरेबल्स, औद्योगिक और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूरसंचार उपकरण शामिल होने की संभावना है।

सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में न केवल ताइवानी फॉक्सकॉन व विस्ट्रॉन (दोनों ऐप्पल के अनुबंध निर्माता) और कोरियाई सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियां हों, बल्कि ऑप्टिमस, डिक्सन और लावा जैसे 'घरेलू चैंपियन' भी शामिल हों। वैष्णव ने कहा कि उन्होंने श्रम मंत्रालय से बड़े कारखाने स्थापित करने के मुद्दों के बारे में बात की है जिसमें एक लाख कर्मचारी हो सकते हैं, और श्रमिकों के लिए आवास परिसर हैं।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की यह तैयारी भी

उन्होंने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय भूमि, बिजली, सड़कों और अंतर्निहित कनेक्टिविटी जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ विशाल एकीकृत विनिर्माण क्षेत्र (1,000 एकड़ तक जा सकता है) के निर्माण के लिए भूमि की पहचान कर रहा है, जो कि चीन और वियतनाम में किए गए आवंटन के अनुरूप है। उद्योग ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

शहद में मिलावट से निपटने के लिए छोटे मधुमक्खी पालकों को संगठित करने में मदद करेगा एनबीएचएम

नयी दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) न केवल शहद उत्पादन के कारोबार में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करेगा बल्कि छोटे मधुमक्खी पालकों को एकजुट कर शहद में मिलावट की समस्या से निपटने में भी मदद करेगा। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, अभिलाक्ष लिखी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना एनबीएचएम का कार्यान्वयन देश में 'मीठी क्रांति' हासिल करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।

उन्होंने एक बयान में कहा, ''एनबीएचएम शहद में मिलावट से निपटने के लिए शहद के लिए ढांचागत सुविधाओं और छोटे मधुमक्खी पालकों को संगठित तरीके से जोड़ने में मदद करेगा।''

अधिकारी ने कहा कि एनबीएचएम का उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाना है और इसके लिए मधुमक्खी पालकों के 100 किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ) केंद्र बनेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) द्वारा सहकारी समितियों नेफेड, ट्राइफेड और एनडीडीबी के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम में

600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनबीबी ने शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों जैसे मधुमक्खी पराग, मधुमक्खी मोम, मधुमक्खी के डंक और प्रोपोलिस की ट्रेसबिलिटी के लिए मधुक्रांति पोर्टल लॉन्च किया है।

देश भर में एनबीएचएम के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देते हुए, एनबीबी के कार्यकारी निदेशक एन के पाटले ने कहा कि मधुमक्खी पालकों और अन्य हितधारकों को वस्तुतः लाभ दिलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ''मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने के लिए यह सलाह दी जाती है कि शहद के उत्पादन के साथ-साथ रॉयल जेली, मधुमक्खी पराग, मधुमक्खी मोम, मधुमक्खी डंक, प्रोपोलिस इत्यादि जैसे अन्य मधुमक्खी उत्पादों का भी उत्पादन किया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि आईसीएआर पूरे भारत में एआईसीआरपी केंद्रों के तहत 'परागण उद्यान' बनाने की राह पर है। उन्होंने कहा कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड में इस तरह का पहला परागण उद्यान स्थापित किया गया है। नेफेड के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक पंकज प्रसाद ने कहा कि उनकी सहकारी संस्था, मधुमक्खी पालकों और शहद प्रसंस्करणकर्ताओं के 65 संकुल और एफपीओ बना रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीडीबी का डेयरी सहकारी समितियों की तर्ज पर शहद एफपीओ बनाने की सोच है ताकि डेयरी सहकारी समितियों और दूध संघों के पास उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं का लाभ मिल सके। ट्राइफेड की महाप्रबंधक सीमा भटनागर ने कहा कि यह सहकारी संस्था पहले से ही देश के आदिवासी हिस्सों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और जंगली शहद की खरीद में शामिल है और उसने वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न देशों को 115 लाख रुपये के शहद का निर्यात भी किया है।

ऑस्ट्रेलिया के ब्लैकमोर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की

- **उड़ान प्लेटफॉर्म पर मल्टीविटामिंस प्रोडक्ट्स की रेंज उपलब्ध होगी**
- **ब्लैकमोर्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उड़ान की मजबूत पहुँच और ई-कॉमर्स विशेषज्ञता से लाभान्वित होगा**

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ऑस्ट्रेलिया स्थित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंद की जाने वाली प्राकृतिक स्वास्थ्य और आहार पूरक कंपनी, ब्लैकमोर्स ने आज भारत में अपने मल्टीविटामिंस प्रोडक्ट्स की श्रृंखला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप (वितरण साझेदारी) की घोषणा की। इस पार्टनरशिप के रूप में ब्लैकमोर्स की प्रीमियम मल्टीविटामिंस प्रोडक्ट्स की रेंज भारत के सबसे बड़े बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'उड़ान' के माध्यम से भारत में स्वतंत्र फार्मेसियों के लिए उपलब्ध होगी।

ब्लैकमोर्स, जो पहले से ही एशिया-पैसिफिक में 12 अन्य बाजारों में कार्यरत है, के लिए भारत एक फोकस ग्रोथ मार्केट है। यह वर्ष 2025 तक 100 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रकृति की उपचार शक्ति से रूबरू कराने की महत्वाकांक्षा लिए हुए है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए शुरुआती लॉन्च प्रोडक्ट्स में हड्डियों की मजबूती और प्रतिरक्षा के लिए ब्लैकमोर्स शाइन पॉवररू डी3, जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए ब्लैकमोर्स ग्लूकोसोग्रीन 1500, आँखों के स्वास्थ्य के लिए ब्लैकमोर्स ब्लू लाइट डिफेंस, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ब्लैकमोर्स बायो कैल्शियम और हृदय के स्वास्थ्य के लिए ब्लैकमोर्स सीओक्यू10 150ष्ट शामिल हैं। आगामी महीनों में कंपनी अतिरिक्त अनुरूप और भी नए प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उड़ान प्लेटफॉर्म पर फार्मा श्रेणी स्वतंत्र फार्मेसियों को 25 से अधिक शहरों को जोड़ने वाले अपने व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट के माध्यम से ब्लैकमोर्स के प्रोडक्ट्स तक सहज पहुँच प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, ब्लैकमोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा फार्मासिस और मेडिकल स्टोर्स में प्रोडक्ट्स की जागरूकता बढ़ाने के लिए सेल्स टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्लैकमोर्स लिमिटेड की एकेडमिक और प्रोफेशनल शाखा, 'ब्लैकमोर्स इंस्टिट्यूट' को वर्ष 2012 में रिसर्च तथा एडुकेशन पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता के साथ स्थापित किया गया था। इसकी टीम में रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स और एजुकेटर्स आदि शामिल हैं, जो साक्ष्य-आधार को व्यावहारिक हैल्थकेयर एडुकेशन और रिसोर्सेज में अनुवाद करते हैं।

ब्लैकमोर्स ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलेस्टेयर सिमिंगटन ने कहा, 'ब्लैकमोर्स लोगों को प्रकृति की उपचार शक्ति से रूबरू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम

पोषक तत्वों से युक्त सामग्री चुनते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट्स उच्च गुणवत्ता वाले और प्रभावी होते हैं, और दुनिया के कुछ सबसे कठोर सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। उड़ान प्लेटफॉर्म पर इसका लॉन्च भारत के शीर्ष शहरों में फार्मेसियों तक पहुँचने का अवसर प्रदान करेगा। विवेक गुप्ता, हेड- फूड एंड एफएमसीजी और फार्मा कैटेगरी, उड़ान, ने कहा, 'हम ब्लैकमोर्स के प्रीमियम मल्टीविटामिंस प्रोडक्ट्स की रेंज को प्लेटफॉर्म पर पेश करके बेहद खुश हैं। यह व्यवस्था प्रमुख ब्रांड्स के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित करने और भारतवर्ष में हमारी गहरी पहुँच और ई-कॉमर्स बाजार की हमारी समझ को देखते हुए प्रमुख फार्मा कंपनियों के लिए भागीदार बनने की क्षमता को रेखांकित करती है। देशभर में फार्मेसियों के साथ हमारा पैमाना, दक्षता और मजबूत संबंध हमें निर्माताओं की वितरण जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अनूठा लाभ प्रदान करता है।'

व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ से भारतीय उत्पादों पर सब्सिडी-रोधी शुल्क हुआ कम: मंत्रालय

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय के तहत गठित व्यापार रक्षा प्रकोष्ठ ने भारतीय उत्पादों पर दूसरे देशों में लगाए जाने वाले सब्सिडी-रोधी शुल्क को नीचे लाने में मदद की है। मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ (टीडीडब्ल्यू) की गतिविधियों से भारतीय निर्यातकों पर दूसरे देशों में लगे सब्सिडी-रोधी शुल्क को 11.67 प्रतिशत से घटाकर 2.82 फीसदी पर लाया जा सका है।

मंत्रालय ने कहा, ''टीडीडब्ल्यू की सतत कोशिशों का नतीजा इस रूप में निकला है कि अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान जारी प्रारंभिक एवं अंतिम नतीजों के एक बड़े हिस्से में न्यूनतम सीमा शुल्क दरें तीन-छह फीसदी के बीच ही रही हैं।'' टीडीडब्ल्यू भारतीय निर्यात पर दूसरे देशों में लगाए जाने वाले सब्सिडी-रोधी शुल्क को तर्कसंगत बनाने के लिए काम करता है। वहीं व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) डंपिंग एवं आयात शुल्कों के खिलाफ जांच करता है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि टीडीडब्ल्यू यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि दूसरे देशों में भारतीय उत्पादों पर कोई व्यापार निषेध न लगे।

वोल्वो ग्रुप इंडिया को वाहनों पर कराधान में कमी की उम्मीद

मुंबई। एजेंसी

वाहन विनिर्माता वोल्वो इंडिया ग्रुप ने एक फरवरी को पेश किये जाने वाले आम बजट में वाहन क्षेत्र के लिए कराधान को कम करने की वकालत की है। वोल्वो इंडिया ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को सर्तक और चुनिंदा रणनीति की जरूरत है। वोल्वो ग्रुप इंडिया और दक्षिण-एशिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कमल बाली ने अपने बजट-पूर्व नोट में कहा कि उद्योग कलपुर्जों के लिए उलट शुल्क ढांचे से बचने के लिए एक पुख्ता नीति की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वोल्वो ग्रुप इंडिया को बजट में बुनियादी ढांचे पर केंद्रित पूंजीगत व्यय, स्वच्छ, हरित और कनेक्टेड लॉजिस्टिक्स पर खर्च जारी रहने की उम्मीद है। इससे एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा। बाली ने कहा कि 2018 में शानदार प्रदर्शन के बाद मोटर वाहन क्षेत्र विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहन उद्योग एक्सल लोड को लेकर नए दिशा-निर्देशों, बीएस-छह नियमों से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रतिबंधों, जिंसों की बढ़ती कीमतों और कलपुर्जों की कमी के कारण आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने से भी उद्योग के प्रदर्शन पर असर पड़ा है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव
मध्यप्रदेश शासन

देश के लिए बलिदान होने वाले
वीर सपूतों को शत्-शत् नमन।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

73वें
गणतंत्र दिवस
की प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

जनभागीदारी से
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
D-18222/21
आकल्पन - मध्यप्रदेश माध्यम/2022

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।